

संविधान सभा

१९५६

इसने पञ्जाब की अवलोकन किया। जिसमें इस
 न्यायालय द्वारा दिनांक 3.8.1990 को प्रकृत उपखण्ड
 अधिकांश संसद को विधित जांच कर प्रकरण में नये सिरे से
 आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया था, लेकिन पञ्जाब की
 पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थी के पिता नानू द्वारा
 उपखण्ड अधिकांश के न्यायालय में इस न्यायालय द्वारा पारित
 आदेश की अनुपालना में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो
 और उपखण्ड अधिकांश द्वारा सुनवाई करने से इनकार कर
 दिया हो। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मूल अधीनस्थ
 नानू पुत्र जल का देहान्त हो चुका है तथा इस न्यायालय
 द्वारा पारित आदेश को 28 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है
 तथा 28 वर्ष की अवधि पश्चात् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
 गया है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। अतः ऐसी
 स्थिति में यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पौषणीय
 नहीं होने से खारिज किया जाता है। पञ्जाब की फैसलें संसद
 को नकार से कम हो। पञ्जाब की बादा तकमिल जाता
 दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र
 अवमानना पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि इस
 न्यायालय द्वारा दिनांक 3.8.1990 को निर्णय पारित किया गया
 था, जिसकी पालना में अपर जिला कलेक्टर (दिलीप) जयपुर
 व तहसीलदार संभारलेक द्वारा कोई कायवाही नहीं की गयी
 है, इसलिये आदेश दिनांक 3.8.1990 की पालना हेतु अप्रार्थी
 संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जावे।

11.6.2018

नबर व
 तारीख
 अहमम जी
 इस दृष्टि की
 तारीख में
 जारी हुए

दृष्टि या कायवाही मय इतिहास जल
6/2018 प्र. पत्र अवमानना
नानू व नाम तहसीलदार

तारीख दृष्टि